रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1759] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2019/ज्येष्ठ 24, 1941
No. 1759] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2019/JYAISTHA 24, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

का.आ. 1967(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4107 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, तवी वन्यजीव अभयारण्य 35.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और मिजोरम राज्य के आइजोल और सर्चिप जिलों में स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य में 83% आरक्षित वन और 27% सरकारी अवर्गीकृत भूमि सम्मिलित है। इसका अधिकांश क्षेत्र 75% खड़ी ढलानों वाला पहाड़ी क्षेत्र और 25% क्षेत्र साधारण ढलानों वाला क्षेत्र है। यहां रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानें हैं;

और, इस अभयारण्य के पारिस्थितिकी, वनस्पति, जीवजन्तु संबंधी और प्राकृतिक महत्व के कारण और वन्यजीवों ओर इसके संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता को देखते हुए मिजोरम राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना सं. बी.12012/1/91-एफएसटी, तारीख 16 नवम्बर, 2001 द्वारा तवी वन्यजीव अभयारण्य को अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, तवी वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता समृद्ध है, और कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक प्रजातियों को आश्रय और संरक्षण प्रदान करता है। यह अभयारण्य आसपास के ग्रामों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है, जो कई नदियों और धाराओं के आवाह क्षेत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

और, तवी वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों की 58 प्रजातियों का संरक्षण और संरक्षा प्रदान करता है जिनमें 29 वृक्ष प्रजातियां, 11 झाड़ियों की प्रजातियां, 5 जड़ी बूटी की प्रजातियां, 6 बांस और रॅतन की प्रजातियां, और 7 ऑर्किड प्रजातियां सम्मिलित हैं। 29 वृक्ष प्रजातियों में थिंगथुपुई (*डायोक्सिलियम गोबरम*), केइफैंग (*मिरिका एसुलेन्टा*), केईपूई (*प्रूनुस जेन्किन्सी*), थिंगसाई (*कास्टानॉपसिस ट्रिबोलियॉइड*), लुम लेर (*प्रूनस नेपोलेंसिस*), डोजो (*एक्सटोलिस हुकेरी*), थेनसेन (*लिथोकारपस पचीफ़ायला*), थेयरलंग (*प्रूनस अंडुलेट*), थेइपलिंगकाख (*ब्रुस्यमिया पॉलिसप्रमी*), थिंगथिआंग (*ओला सैलिसिफोलिया*), थाल (*क्रैक्रस डीलाटाटा*), तुफ़ार (*सेफालोटाटस ग्रिफिथी*), फुओनबर (*मार्कोपेनाक्स डिस्पिरमस*), सुपरबुल (*सिनामोमम ग्लौसेस्केंस*), सियाल्मा (*हेलिसिया एक्सेल*), नौथक (*लितसी सेमेकरपीफोलिया*), थिंगबुहचन्ग (*मैचिलस एसपीपी.*), हिंगजौ (*बेटुला सिलिंड्रोस्ताची*), घलचन (*एरीओबोट्रिया बेंगलेंसिस*), बुलपुई (*एल्सोडाफने पेटीओलारिस*), थिंगप्यूइथिंग (*लिथोकारपस एलिगेंस*), थिंग्सहलुम (*विटेक्स कैनेसिन्स*), तस्पाता (*सिनामामम तमला*), कावपुई (*साइकास पेक्टिनटा*), थिंग्सपू (*डायोएक्सिलम ऑलियारिया*), खुंगथुल (*एल्डेओडाफनी पेटिओलारिस*), तुयितित (*एंटिदेसमा बुनियस*), मु स्यू (*सिमप्लोकोस थेफोलिया*) और हेल (*ज़ज़ीफ़स इन्कर्व*) आदि सम्मिलित हैं। 11 झाड़ी प्रजातियों में खूप-अल (*वर्नोनिया वोल्कामेरियाफोलिया*), थिंगसाईघल (*कोफिया खासीयाना*), वाहरिथेई (*अर्दीसिया मैक्रोकारापा*), मुपा (*रुबस नेवेस*), वेकप (*मुसांडा एसपीपी*), उइफॉमरिंग्रु (*डेसमोडियम ट्रिगुएट्रम*), सरज़ुक (*एलाकनगुस क्यूडेट*), रलसमकुई (*अनकारिया लाविगाटा*), खुपनल (*पिलैइ सिमरिया*), पहरुअल (*मेसा अंडमानिका*) और ज़ुतिल (*लेपिसन्थस सुंगेलांसिस*) आदि, सम्मिलित हैं। 5 जड़ी बूटी प्रजातियों में कटचल (*माइक्रोलेपीया स्ट्रीगोसा*), थिप (*सक्लेरिया लेविस*), हन्ना ह्रत (*थालिक्टर पंडनुम*), बुल बाक (*ब्रैसिका ओलेरैसा*) और राम टिंग (*इचिनाकेन्थस एंडसोनी*) सम्मिलित हैं। बांस की 6 प्रजातियों में फर(*चिमनोबाम्बुसा कॉलोसा*), रॉन्गल (*स्कीज़ोस्टाच्यम फूशियानम*), चाल (*स्कीज़ोस्टाच्यम पॉलीमोरफम*), सायरिल (*डिनोचलोआ कैम्पैक्टफ्लोरा*), हरुईपुई *(कैलमास ईरेक्टस)* और कावरतई *(कैलमास एसपीपी.)* आदि सम्मिलित है। ऑर्किड की 7 प्रजातियों में सेनहरी (*रेणेंथेरा इम्स्चुतियाना*), बान सेई/लाइहांग (*डेंड्रोबियम फ़िम्ब्रियाटम*), लॉह लेई (*वंद कोरुले*), नाउबान पर वर (*कोलॉजीन निटिडा*), नाउबान-नावी-नाक (*प्लेईवन प्रायकोक्स*), नाउबान (*डेंड्रोबियम अपिलम*) और नाउबन पारटियल *(एस्मेरलाडा क्लारकेइ)* सम्मिलित हैं;

और, यह अभयारण्य जीवों की 19 प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें 4 प्रकार की मांसाहारी प्रजातियां, 2 अनगलित की प्रजातियां, 7 सर्वाहारी प्रजातियां, 4 प्राइमेट प्रजातियां और 2 छोटे अन्य स्तनधारियों की प्रजातियां जिनमें सामान्य तेंदुआ (*पैन्थेरा पार्डस*), स्वर्ण बिल्ली (*कैटपूमा टेंमिन्की*), जंगल बिल्ली (*फेलिस चॉस*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनायलुरस बंगालसिस*), गोरल (*नामोरेडस गोरल*), सेरो (*नामोरेडस सुमात्रानसिस*), एशियाटिक काला भालू (*उर्सस थिबेटनस*), सन बीयर (*हेलारकोटोस मलयानस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइन*), स्मॉल टूथेड फेरेट बेजर (*मेलोगले मॉस्चाटा*), सामान्य मुसंग-ज़बबूआंग (*पैराडोक्सुरस हेर्मप्रोदिटस*), बिंटूरॉन्ग-जम्फू (*आर्क्टिकटिस बिंटुराँग*), रेसस मकाक-ज़ॉग (*मकाका मुलाटा*), असम मकाक-ज़ॉग (माकाका एडमांस्सिस), कैपड लंगूर-एनगौ *प्रेस्बिटीस पिलेटस, हूलॉक गिबोन-हौचुक* (*हीलोबेट हूलॉक*), मलयियन विशालकाय गिलहरी-अतारंग (*रतुफा बायकोलर*) और पल्ला गिलहरी (*कैलोसिसियस एरिथ्रूस*) आदि सम्मिलित हैं।

और, तवी वन्यजीव अभयारण्य पक्षियों से समृद्ध है और 40 महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जिनमें बांस तीतर-वाहला (*बम्बूसीकोला फिचि*), भूटान मयूर तीतर-विरिहौ (*पॉलीप्लेक्सटन बिलिककरतम*), कोलेटेड ओल्ट-हर्न्गकिर (*ग्लक्इडीम ब्रोडी*), भारतीय चितकबरी धनेश-वाहा (*एन्थ्रोकोकेरस अल्बिओरोरिसिस*), सफेद गलेदार भूरा धनेश-वांगई (*पीटीलोलामास टिक्केली*), हूडेड पिट्टा-बुर्कावम (*पिटा सोंर्डिडा*), ब्लैक ईगल-मू-लंगडूप (*इकिटिनात्स मिलिएन्सिस*), वेडटेल्ड कबूतर-वाहुइ (*ट्रेनन स्फेनुरा*), बार्टेलियल मुर्गा कबूतर-तृमी-मेईसेई (*मैक्रोपीयिया अनछल*), इंपीरियल कबूतर-बुल्लुट (*दुकुला बदिया*), गोल्डन गले बारबेट-ज़ो-तुक्लो (*मेगलैमा फ्रैंकलिनी*), रुफस बेलिड बुलबू-व्हाइएप (*हाइपिसिपेट्स मैकललेन्डी*), कोरलबिलिड स्किमीटर बब्बलर-नेगवानपेय्यूअल (*पोमेटोरिनीस फेरैंविनोसस*), फिंचबल्ड बुलबुल-रावी-रावी (*स्पिज़िक्सस कैनिफ्रॉन्स*), नीली पंखों वाला शिव-चंग्रुल (*मिनला साइनाओर्पेटेरा*), ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रॉन्गो-वाकूल (*डाइक्रुरस हॉट्ट्रॉटोटस*), हेयरकोरस्ट ड्रोंगो-कुल्हेर (*डाइक्रुरस हॉट्रॉटोटस*), ग्रीन मैग्पी-डवाण्टियांग (*सीसा सिनेमसिस*), स्पॉटेड फॉर्कटेल-चीनरंग

(*एनिकुरस मैकुलेटस*), स्लेटीबैक्ड फॉर्कटेल-चिंगरैंग (*एनिकुरस मैकुलाटस*), लिटिल फॉर्कटेल-चिन्नान्टे (*एनिकुरस स्किस्टेसस*), गोल्ड सनबर्ड-डेविथमर (*एथोपैगा गॉल्डिएई*), फायरब्रेस्टेड फ्लावर पेकर-टिक-टिक (*डिकाइम इग्नेसटस*), ब्लैक चिन्ड यूहिना-तेहहेक (*युहिना निग्रिमेंटा*), गोल्डन हेडड टेलरबर्ड-डाइकैट (*ऑर्थोटॉमस कोकुलेटस*), बड़े लकड़ी लहटोरा-ल्लेकबुर (*टिफ्रोडोर्निस वीरगाटस*), येलो थ्रोटेड मिनिवेट-बॉंग (*पिरिक्रोकोटस सोलरिस*), बड़े कोयल-लहटोरा-इरिलीक/बावंगपुई (*कोरासिना नव-हॉलैंडिया*), ग्रेट स्लेटी कठफोडवा -तालहसाई (*मुलरिपिकस पेल्वेरुलुएंटस*), वेलवेट-फ्रंटेड नचच-सुकटेल (*सीट्टा फ्रंटटालिस*), व्हाइटटेल्ड नचर्च-सुकलेट(*सिट्टा हिलालायांसिस*), स्पेक्लेट प्यूलेट-ल्यूंगट्यूबुह (*पिकमुस इंडोमिनेटस*), ग्रे सिबिया-वासीर (*हेटोरोफैसिया ग्रैलिसिस*), स्ट्रीप लाफिंग थ्रश-ज़ोवा (*गैरुलक्स वर्गाटस*), हॉजसन फ्रोगमाथ-वाबक (*बैटैचेस्टोमस हॉजसॉनी*), ग्रे विंगेड ब्लैकबर्ड-ज़ोचिपुई (*टर्डस बुलबुल*), हिमालयी ग्रीन फिंच-टिप (*कार्डुएल्स स्पिनॉयड*), स्वर्ण हेडेड टेलर पक्षी-हनहफन (*ऑर्थोटॉमस कुक्कुललस*), बे उल्लू-तांगगै (*फोडिलस बैडीस*) और पिग्मी ब्रे-बब्बलर-मुंचे-अरपुइ (*फोनेपेगा पुसिला*) आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीवों की 7 स्थानिक प्रजातियां हैं जिनमें हूलॉक गिब्बन, सेरो, कैप्ड लंगुर**,** मलाया विशाल गिलहरी, थिंगथुपुई**,** ग्रिफ़िथ प्लम यू और बॉक्स मर्टल शामिल हैं। इनमें से तीन प्रजातियां: लॉक गिब्बन**,** सेरो और कैप्ड लंगुर दुर्लभ**,** लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं**;**

और, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजन्तु और पक्षी-जीव रहते हैं, और यह मिजोरम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षक और आश्रय स्थल है;

और, तवी वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य में आइजोल सेरछिप तवी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित 16.05 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं:-** (1) तवी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित 16.05 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन होगा।

(2) तवी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) तवी वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का तवी वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम मुमंथा आंशिक रूप से सम्मिलित है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग

(xii) राजमार्गो; और

(xiii) मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

IndiaCode

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

(i)	आइजोल जिले का उपायुक्त	-अध्यक्ष;
(ii)	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(viii)	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;

(x)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xi)	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xv)	प्रकृति संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे मिजोरम सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जायेगा	–सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जाएगा	–सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव विविधता का विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जाएगा	–सदस्य;
(xix)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आइजोल	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

IndiaCode

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/20/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

तवी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: उत्तरी सीमा विस्तृत है और 800 मीटर (92°55'1.109"पू, 23°34'36.026"उ) दूर ववमारवाह लुई की ओर जाती है। यह तुईखुर लुई (92°56'58.721"पू, 23°33'56.422"उ) में मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से तुईखुर लुई के उत्तर में 800 मीटर आरंभिक बिंदु तक जाती है।

पूर्व: तुईखुर लुई से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अभयारण्य सीमा के साथ 100 मीटर तक है और वैदन लुई (92°57'41.421"पू, 23°33'23.893"उ) को पार करती है। यह दक्षिण में जाती है फिर यह खुई लुई (92°58'34.397"पू, 23°32'29.627"उ) पहुँचती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तुई खुर लुई से अभयारण्य सीमा से 100 मीटर दूर तक जाती है। खुई लुई से यह अभयारण्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर 500 मीटर तक जाती है। और फिर यह फैसेन लुई(92°59'15.804"पू, 23°30'54.746"उ) से मिलती है। खुई लुई से फैसेन लुई तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर है।

दक्षिण: फैसेन लुई से पश्चिम की ओर हमुनथा ग्राम तक जाती है और हमुनथा ग्राम के कुछ भाग को पार करके यह सजा लुई (92°56'1.758"पू, 23°30'0.917"उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई फैसेन लुई से सजा लुई तक अभयारण्य सीमा से 500 मीटर है।

पश्चिम: सजा लुई से यह उत्तर की ओर जाकर तुईकुम लुई (92°55'41.12" पू, 23°30'38.163"उ) को पार करती है और अभयारण्य सीमा के साथ 800 मीटर तक फैली है। यह आरंभिक बिंदु पर खुई लुई से मिलकर समाप्त होती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई सजा लुई से अंतिम बिंदु तक अभयारण्य सीमा से 800 मीटर है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन विस्तार की चौड़ाई तवी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 0.1 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक परिवर्तित होती है।

उपाबंध-II

भू स्थिति प्रणाली की दृष्टि से तवी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

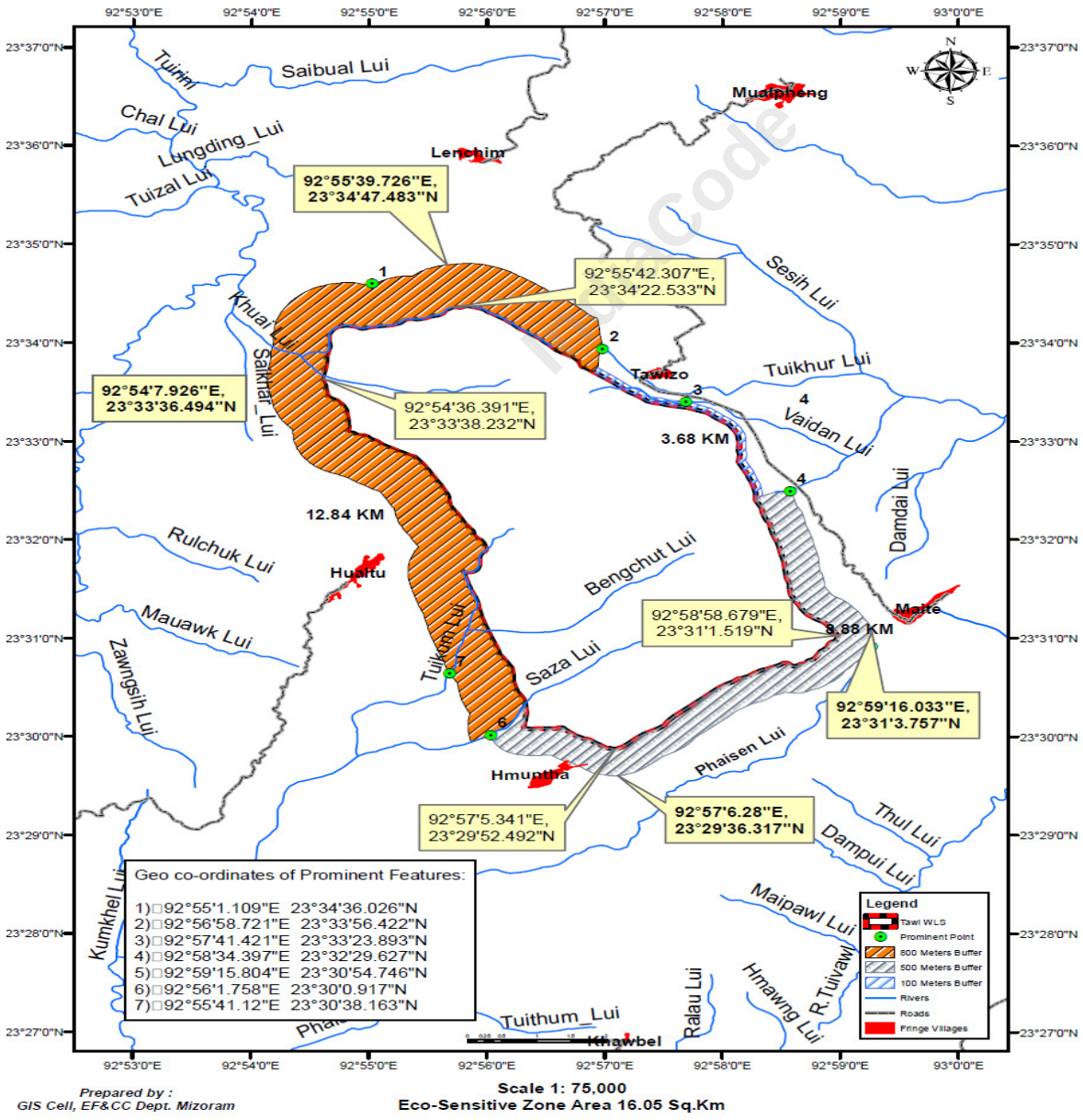
क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	23°34'22.533"उ	92°55'42.307"पू
2	पूर्व	23°31'1.519"उ	92°58'58.679"पू
3	दक्षिण	23°29'52.492"उ	92°57'5.341"पू
4	पश्चिम	23°33'38.232"उ	92°54'36.391"पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	23º 34' 48.543" उ	92º 55' 50.515" पू
2	पूर्व	23º 31' 2.748" उ	92º 59' 15.434" पू
3	दक्षिण	23º 33' 37.937" उ	92º 54' 7.885" पू
4	पश्चिम	23º 29' 36.254" उ	92º 57' 4.841" पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ तवी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2019

S.O. 1967(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 4107(E), dated the 28th December, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29th December, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Tawi Wildlife Sanctuary (WLS) is spread over an area of 35.75 square kilometers and situated under the Aizawl and Serchhip Districts in the State of Mizoram. The Wildlife Sanctuary contains 83% Reserve Forest and 27% Government unclassed land. Most of the area is hilly terrain with 75% steep slope and 25% of gentle slope with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Tawi Wildlife Sanctuary was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* Notification No. B.12012/1/91-FST dated the 16th November, 2001;

AND WHEREAS, the Tawi Wildlife Sanctuary is rich in biodiversity, and provides shelter and protection to many rare, endangered and threatened (RET) and endemic species. It also plays an important role as a catchment area for many rivers and streams that act as a main source of a drinking water for the villages around the sanctuary;

AND WHEREAS, the Tawi Wildlife Sanctuary conserves and supports about 58 species of flora including 29 tree species, 11 species of shrub, 5 species of herb, 6 species of bamboo and rattans, and 7 species of orchids. The 29 tree species include Thingthupui (*Dysoxylum gobarum),* Keifang (*Myrica esulenta*), Keipui (*Prunus jenkinsii*), Thingsai (*Castanopsis tribuloides*), Lum ler (*Prunus nepaulensis*), Dozo (*Xantolis hookeri*), Thensen (*Lithocarpus pachyphylla*), Theiarlung (*Prunus undulate*), Theipalingkawh (*Bruinsmia polysperma*), Thingthiang (*Olea salicifolia*), Thal (*Quercus dilatata*), Tufar (*Cephalotatus griffithii*), Phuanberh (*Marcopanax dispermus*), Saperbul (*Cinnamomum glaucescens*), Sialhma (*Helicia excels*), Nauthak (*Litsea semecarpifolia*), Thingbuhchang (*Machilus* spp.), Hringzau (*Betula cylindrostachy*), Nghalchhun (*Eriobotrya bengalensis*), Bulpui (*Alseodaphne petiolaris*), Thingpuithing (*Lithocarpus elegans*), Thingsaihlum (*Vitex canescens*), Tespata (*Cinnamemum tamala*), Kawkpui (*Cycas pectinata*), Thingsaphu (*Dysoxylum alliaria*), Khuangthulh (*Alseodaphne petiolaris*), Tuaitit (*Antidesma bunius*), Mu sau (*Symplocos theafolia*) and Hel (*Ziziphus incurve*). The 11 shrub species include Khup-al (*Vernonia volkameriaefolia*), Thingsainghal (*Coffea khasiana*), Vahritthei (*Ardisia macrocarpa*), Hmupa (*Rubus niveus*), Vakep (*Mussaenda* spp.), Uifawmaringruh (*Desmodium triguetrum*), Sarzuk (*Elacagnus caudate*), Ralsamkuai (*Uncaria laevigata*), Khupnal (*Pilea symeria*), Pawhrual (*Maesa andamanica*) and Zutil (*Lepisanthus sungalensis*). The 5 herb species include Katchal (*Microlepia strigosa*), Thip (*Scleria levis*), Hnah Hrat (*Thalictrum punduanum*), Bul bawk (*Brassica oleracea*) and Ram ting (*Echinacanthus andersonii*). The 6 species of bamboo include Phar (*Chimnobambusa callosa*), Rawngal (*Schizostachyum fuchsianum*), Chal (*Schizostachyum polymorphum*), Sairil (*Dinochloa campactiflora*), Hruipui (*Calamus erectus*) and Kawrtai (*Calamus* spp.). The 7 species of orchids include Senhri (*Renanthera imschootiana*), Ban sei/Laihang (*Dendrobium fimbriatum*), Lawh lei (*Vanda coerulea*), Nauban par var (*Coelogyne nitida*), Nauban-nawi-nawk (*Pleione praecox*), Nauban (*Dendrobium aphyllum*) and Nauban partial (*Esmeralda clarkei*);

AND WHEREAS, the Sancturay supports 19 fauna species including 4 species of carnivores, 2 species of ungulates, 7 omnivores species, 4 species of primates and 2 species of other small mammals including Common Leopard (*Panthera parades*), Golden cat (*Catpuma temmincki*), Jungle cat (*Felis chaus*), Leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), Goral (*Naemorhedus goral*), Serow (*Naemorhedus sumatraensis*), Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus*), Sun Bear (*Helarctos Malayanus*), Jackal (*Canis aureus*), Wild dog (*Cuonalpines*), Small toothed Ferret Badger (*Melogale moschata*), Common Palm Civet-Zawbuang (*Paradoxurus hermaphroditus*), Binturong-Zamphu (*Arctictis binturong*), Rhesus macaque-Zawng (*Macaca mulata*), Assamese macaque-Zawng (*Macaca assamensis*), Capped langur-Ngau (*Presbytis pileatus*, Hoolock gibbon-Hauhuk- (*Hylobate hoolock*), Malayan giant squirrel-Awrrang (*Ratufa bicolor*) and Palla's Squirrel (*Callosciurus erythraeus*);

AND WHEREAS, the Tawi Wildlife Sanctuary is rich in avifauna and supports 40 important birdspecies like Bamboo Partridge-Vahlah (*Bambusicola fytchii*), Bhutan Peacock pheasant-Varihaw (*Polyplexton bicalcaratum*), Collared Owlet-Hrangkir (*Glaucidium brodiei*), Indian pied Hornbill-Vahai (*Anthracoceros albirostris*), White throated brown Hornbill-Vangai (*Ptilolaemus tickelli*), Hooded pitta-Buarchawm (*Pitta sordida*), Black Eagle-Mu-Lungdup (*Ictinaetus malayensis*), Wedgetailed Pigeon-Vahui (*Trenon sphenura*), Bartailed Cuckoo dove-Thumi-meisei (*Macropygia unchall*), Imperial Pigeon-Bullut (*Ducula badia*), Golden throated Barbet-Zo-Tuklo (*Megalaima franklinii*), Rufous Bellied Bulbu-Vachiap (*Hypsipetes mcclellandii*), Coralbilled Scimitar Babbler-Ngalvapual (*Pomatorhinis ferruginosus*), Finchbilled Bulbul -Rawi-rawi (*Spizixos canifrons*), Blue winged Siva-Changrual (*Minla cyanouroptera*), Greater racket tailed Drongo-Vakul (*Dicrurus hottentottus*), Haircrested Drongo-Kulherh (*Dicrurus hottentottus*), Green magpie-Dawntiang (*Cissa chinemsis*), Spotted forktail -Chinrang (*Enicurus maculatus*), Slatybacked forktail-Chinrang (*Enicurusscouleri*), Little forktail-Chinrangte (*Enicurus schistaceus*), Gould's Sunbird-Dawithiamar (*Aethopyga gouldiae*), Firebreasted flower pecker -Tik-Tik (*Dicaem ignipectus*), Black chinned Yuhina -Tehhek (*Yuhina nigrimenta*), Golden Headed Tailorbird-Daikat (*Orthotomus cucullatus*), Large wood Shrike-Thlekbur

(*Tephrodornis Virgatus*), Yellow throated Minivet-Bawng (*Piricrocotus solaris*), Large cuckoo-Shrike-Irliak/Bawngpui (*Coracina novae-hollandiea*), Great Slaty Woodpecker-Thlohsai (*Mulleripicus pulverulentus*), Velvet-fronted Nutchatch-Suklet (*Sitta frontalis*), Whitetailed Nutchatch -Suklet (*Sitta himalayansis*), SpecletPiculet -Luangtubeuh (*Picummus innominatus*), Grey Sibia -Vasir (*Heterophasia gracilis*), Striped laughing thrush-Zova (*Garrulax virgatus*), Hodgson's Frogmouth-Vabak (*Batrachestomus hodgsoni*), Grey winged Blackbird -Zochippui (*Turdus bulbul*), Himalayan Green finch -Tep (*Carduelis spinoides*), Golden headed Tailor Bird-Hnahfun (*Orthotomus cuccullatus*), Bay Owl-Tahngai (*Phodilus badius*) and Pigmy Wren-Babbler-Hmunchhe-Arpui (*Pnoepyga pusilla*);

AND WHEREAS, the Sanctuary also have 7 endemic species of flora and fauna including Hoolock gibbon, Serow, Capped langur, Malayan giant squirrel, Thingthupui, Griffith's plum yew and Box myrtle. Three of these species: Hoolock gibbon, Serow and Capped langurare listed under rare, endangered and threatened (RET) category;

AND WHEREAS, the Tawi Wildlife Sanctuary is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Tawi Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.1 kilometers to 0.8 kilometers around the boundary of Tawi Wildlife Sanctuary, in Aizawl and Serchhip districts in the State of Mizoram as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1) The Eco-sensitive Zone shall be 16.05 square kilometres with extents varying from 0.1 kilometre to 0.8 kilometres around the boundary of the Tawi Wildlife Sanctuary;

   (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone around Tawi Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**;

   (3) The geo-coordinates of Tawi Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as **Annexure-II**;

   (4) The map of Tawi Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**;

   (5) The village Hmuntha partially falling in the Eco-sensitive Zone.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development ;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Mizoram State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

IndiaCode

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	Deputy Commissioner of Aizawl District	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Land Revenue & Settlement Department	Member;
(iii)	Representative of Rural Development Department	Member;
(iv)	Representative of Agriculture Department	Member;
(v)	Representative of Local Administration Department	Member;
(vi)	Representative of Public Works Department	Member;
(vii)	Representative of Public Health Engineering	Member;
(viii)	Representative of Fishery Department	Member;
(ix)	Representative of Industries Department	Member;
(x)	Representative of Police Department	Member;
(xi)	Representative of Power & Electricity Department	Member;
(xii)	Representative of Animal Husbandry & Veterinary Department	Member;
(xiii)	Representative of Soil & Moisture Conservation Department	Member;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(xv)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Mizoram	Member;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
(xvii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xviii)	One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xix)	Deputy Conservator of Forest, Wildlife, Aizawl	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/20/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'.

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TAWI WILDLIFE SANCTUARY

NORTH : The Northern boundary extends and follows Vawmhrawh Lui at a distance of 800 m (92°55'1.109"E, 23°34'36.026"N) till it meets Tuikhur Lui (92°56'58.721"E, 23°33'56.422"N). The width of the Eco-sensitive Zone from the starting point of North to Tuikhur Lui is 800 m away from the Sanctuary boundary.

EAST: From Tuikhur Lui the ESZ boundary goes along the sanctuary boundary at an extent of 100 m and crosses Vaidan Lui (92°57'41.421"E, 23°33'23.893"N). It goes south till it reaches Khuai Lui (92°58'34.397"E, 23°32'29.627"N). The Eco-sensitive Zone boundary from Tuikhur Lui to Khuai Lui is 100 M away from the sanctuary boundary. From Khuai Lui it goes South along the sanctuary boundary at an extent of 500 m till it meets Phaisen Lui (92°59'15.804"E, 23°30'54.746"N). The width of the Eco-sensitive Zone from Khuai Lui to Phaisen Lui is 500 m away from the sanctuary boundary.

SOUTH: From Phaisen Lui it goes West towards the Hmuntha village and after crossing some part of the Hmuntha village it meets Saza Lui (92°56'1.758"E, 23°30'0.917"N). The width of the Eco-sensitive Zone boundary from Phaisen Lui to Saza Lui is 500 m away from the sanctuary boundary.

WEST: From Saza Lui it goes North and crosses Tuikum Lui (92°55'41.12"E, 23°30'38.163"N) and goes along the sanctuary boundary at an extend of 800 m and meets Khuai Lui and ends at the starting point. The width of the Eco-sensitive Zone from Saza Lui to the end point is 800 m away from the sanctuary boundary.

The width of the Eco-sensitive Zone extent varies from 0.1 km to 0.8 km from the Tawi Wildlife Sanctuary boundary.

ANNEXURE-II

GEO-COORDINATES OF THE TAWI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN TERMS OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM

India Code

GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA BOUNDARY

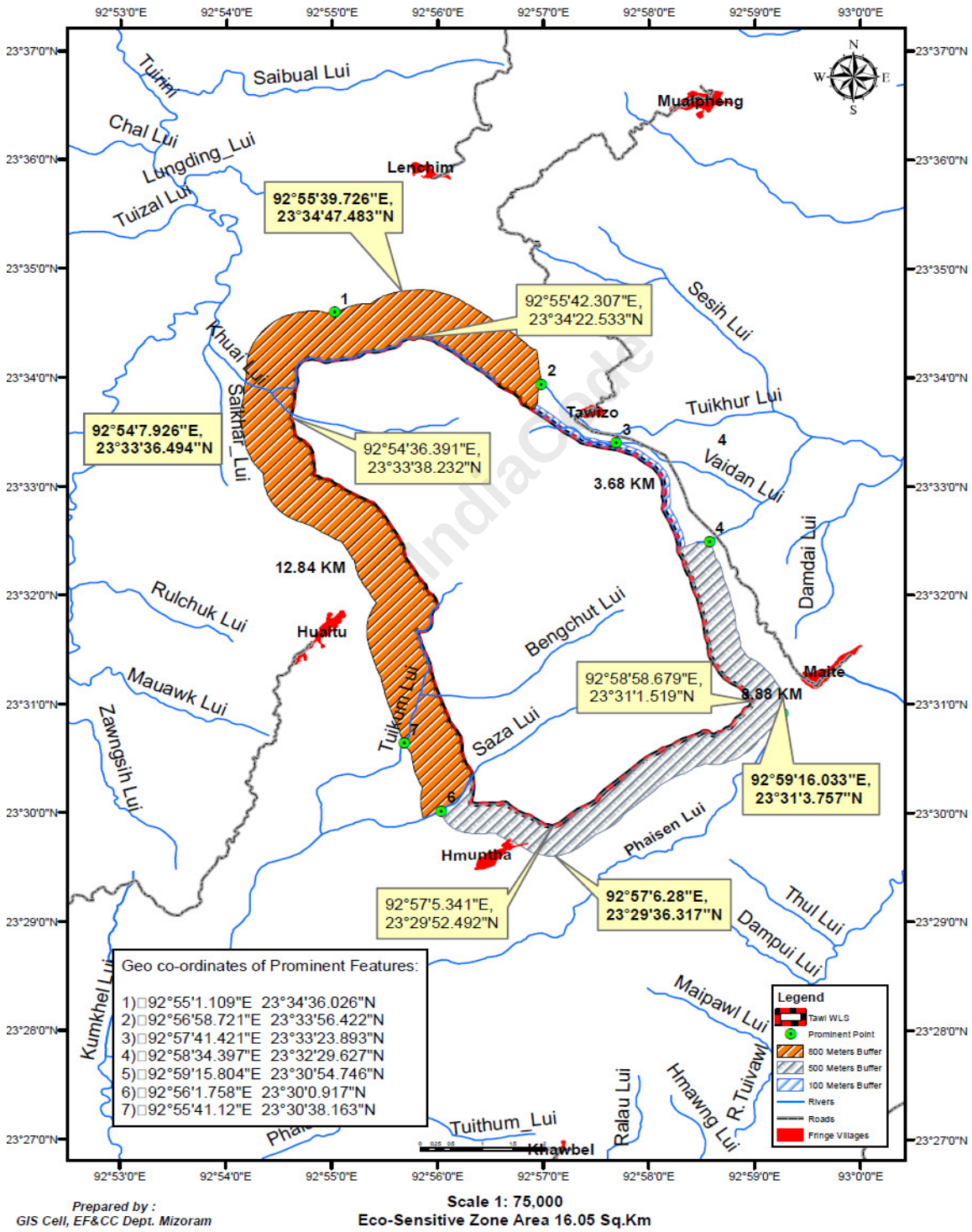
Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	23°34'22.533"N	92°55'42.307"E
2	East	23°31'1.519"N	92°58'58.679"E
3	South	23°29'52.492"N	92°57'5.341"E
4	West	23°33'38.232"N	92°54'36.391"E

GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	23° 34' 48.543"N	92° 55' 50.515"E
2	East	23° 31' 2.748"N	92° 59' 15.434"E
3	West	23°33' 37.937"N	92° 54' 7.885"E
4	South	23°29' 36.254"N	92° 57' 4.841"E

ANNEXURE-III

MAP OF THE TAWI WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES



ANNEXURE –IV

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.17 18:52:33 +05'30'